अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI
TEL.

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-ईआरटीआई/165/2017-18

19 मार्च, 2018

सेवा में,

श्री वी. के. राजन,
उपसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री ब्रजराज कृष्ण गुप्ता, समाज सेवी निवासी 1252/1, माधवपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश का 05.03.2018 का इस कार्यालय में 08.03.2018 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रूपये का पो.आ.सं. 36F 600431 संलग्न कर संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत स्वयं को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाने व अन्य विषयों की जानकारी चाही है। चूंकि पत्र की विषय-वस्तु गृह मंत्रालय से संबंधित है, अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक को मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जो इस विषय के निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री ब्रजराज कृष्ण गुप्ता, समाज सेवी निवासी 1252/1, माधवपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

SPEED

सेवा में,

महामहिम राष्ट्रपति महोदय
भारत सरकार दिल्ली

महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय
भारत सरकार दिल्ली

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

आवेदक

1. प्रार्थी एक भारतीय नागरिक है। प्रार्थी द्वारा अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिये भारत सरकार के व उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय महाअनुभव महामहिम राष्ट्रपति महोदय उप राष्ट्रपति महोदय, प्रधानामंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, केन्द्रीय कानून मंत्री, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख सचिव गृह, उच्च न्यायलय मुख्य न्यायधीश इलाहाबाद, उच्चतम न्यायलय मुख्य न्यायधीश सुर्पीम कोर्ट दिल्ली पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सरकार महोदय, कैबिनेट कानून मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, ऐ०डी०जी० कानून व्यवस्था मेरठ महोदय, पुलिस महा निरीक्षक मेरठ जोन महोदय, मेरठ मण्डल आयुक्त मेरठ महोदय, जिला अधिकारी महोदय, व वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक महोदय से जन सूचना मांगी गयी।
2. सुरक्षा की गारंटी देने में स्थानीय प्रशासन की लावरवाही किस षड़यन्त्र की तहत है।
3. स्थानीय प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार से बड़ा है।
4. केन्द्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार से स्थानीय प्रशासन अपने को बड़ा मानता है।
5. प्रार्थी की अगर हत्या होती है तो उसका जवाब देही किस अधिकारी की होगी।

10 रू० का पोस्टल आर्डर संख्या 36F/600431

दिनांक - 05-03-2018

श्री के शर्मा
प्रार्थी
बृजराजकृष्ण